जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर
Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 336 प्रभात जालोर, गुरुवार 13 मार्च, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्ष के नेताओं को सटीक जवाब दिये

उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ व सीएमआर के गृह प्रवेश में विपक्ष के नेताओं के नहीं आने पर सवाल उठाया

- मुख्यमंत्री ने कहा, जनता सब जानती है, पेपर लीक किसके राज में हुए। बजरी की गलत लीज़ किसने दी। कौन तख्ती लगाकर आया। किसने कहाँ खूब खाया। किसको निकम्मा-नकारा, क्या-क्या शब्द बोले गये। किसके राज में मिनी सीएम घूम-घूमकर भ्रष्टाचार फैलाते थे।
- मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब से राजस्थान दिवस हिन्दू नव वर्ष पर मनाया जायेगा तथा अगले वर्ष 26 हजार पदों पर भर्ती की जायेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में 26 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की जाएगी। इसमें शिक्षक, वन विभाग के कर्मचारी, पुलिस सहित अन्य विभागों के पद शामिल हैं। वहीं, अब हर साल 30 मार्च की जगह हिंदू नववर्ष पर राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही, 19 फरवरी को पेश किया गया बजट विधानसभा में पास हो गया है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए 5 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और वह पेपर मेरे पास है। चुनाव का समय था, हम भी बिजी थे, लेकिन टास्क फोर्स बना दी है।

सीएम ने दौसा और बालोतरा में नगर विकास न्यास (यूआईटी) बनाने की घोषणा की है। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पेश कर रही थीं तो विपक्ष के नेताओं के चेहरे पर उतार-चढ़ाव देखा गया था। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने 28 मिनट तक इधर-उधर की बातें की, लेकिन बजट पर बातचीत नहीं हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्स्टीट्यूशन क्लब का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय हुआ था। कुछ दिन पहले इस क्लब का शुभारंभ था, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने इसका बहिष्कार कर दिया। कहीं हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ उनके ही परिवार के सदस्यों ने षड्यंत्र तो नहीं कर दिया। नेता प्रतिपक्ष आते तो लोकसभा अध्यक्ष से लेकर सबके साथ बैठने का मौका मिलता। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब वाले दिन मुझे इसलिए दुख हुआ, क्योंकि वहां पर विपक्ष के नेताओं और विधायकों का आना बहुत जरूरी था और यह अच्छा होता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएमआर में गृह प्रवेश के वक्त भी कांग्रेस विधायकों को बुलाया था, मैंने आपको घर पर बुलाया था, कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेता और विधायकों को नहीं देखकर दुख हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सब जानती है कि पेपर लीक किसके राज में हुए? बजरी की गलत लीज किसने दी? कौन तख्ती लगाकर आया। किसने कहां खूब खाया। किसको निकम्मा-नकारा क्या-क्या शब्द बोले गए? किसके राज में मिनी सीएम घूम-घूमकर भ्रष्टाचार फैलाते थे।

मुख्यमंत्री ने धारीवाल पर तंज करते हुए कहा कि कोटा उत्तर से आने वाले सदस्य को अब महिलाओं की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। इनके लिए तो यही कहूंगा कि देर आए, दुरुस्त आए। आपकी महिलाओं के प्रति भावनाओं से सब परिचित हैं।

अवकाश की सूचना

होली के पावन पर्व पर राष्ट्रदूत कार्यालय में 13 व 14 मार्च 2025 को अवकाश रहेगा। अतः अगला अंक 16 मार्च 2025 को प्रकाशित होगा।

-व्यवस्थापक

'शरीर पर जन्मजात निशान के कारण अयोग्य घोषित नहीं कर सकते'

- हाई कोर्ट ने पैरामिलिट्री फोर्सेज़ की भर्ती पर आदेश जारी किये।

जयपुर, 12 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए आयोजित भर्ती में महिला अभ्यर्थी को उसके पीठ पर जन्मजात काले निशान के कारण अयोग्य घोषित करने को गलत माना है। इसके साथ ही, अदालत ने अन्य कारण से अपात्र नहीं होने पर महिला अभ्यर्थी को चार सप्ताह में नियुक्ति देने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रामकला वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने मामले में मेडिकल बोर्ड के आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने माना कि बर्थ मार्क से गर्म और आर्द्र जलवायु में जलन पैदा हो सकती है और इससे ड्यूटी में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जबकि स्वतंत्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार, बर्थ मार्क से कोई जोखिम नहीं होगा। ऐसे में याचिकाकर्ता को अनफिट करार देने का कोई चिकित्सीय कारण नहीं है।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद और सुनील कुमार सैनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 24 नवंबर, 2023 को पैरामिलिट्री फोर्सेज में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती निकाली थी, जिसकी 7 मार्च, 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता पास हो गई। वहीं, 8 नवंबर को हुए फिजीकल में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एयरटेल (सुनील मित्तल) के बाद जिओ (मुकेश अंबानी) ने भी स्टारलिंक से अनुबंध किया

अब तक दोनों कम्पनियां, एयरटेल व जिओ, स्टारलिंक के भारत में प्रवेश के घोर विरोधी थीं, पर, दोनों ने यू-टर्न करते हुए, स्टारलिंक से पूर्ण सहयोग करने का मन बना लिया है

- एलन मस्क की कम्पनी स्टारलिंक, विश्व में करीब सौ देशों में स्टारलिंक कम्युनिकेशन सैटलाइट पर आधारित सेवा प्रदान कर रही है।
- जैसा कि विदित ही है, सैटलाइट पर आधारित दूर संचार सेवा उपलब्ध कराने वाली सभी कम्पनियां, उन सैटलाइट्स का उपयोग करती हैं, जो पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर दूरी पर हैं। परन्तु, जिन सैटलाइट्स का स्टारलिंक उपयोग करती है, वो केवल 550 किलोमीटर दूरी पर है। अतः, स्टारलिंक की व्यवस्था में इन्टरनैट मैसेज बहुत जल्दी उपभोक्ता के पास पहुँच जाते हैं, अन्य कम्पनियों के सिस्टम की तुलना में।
- प्र.मंत्री मोदी की पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान एलन मस्क, प्र.मंत्री से मिले थे, तभी से चर्चाएं जोरों पर थीं कि शीघ्र ही स्टारलिंक को भारत में काम करने की इजाज़त मिलेगी। इस मुलाकात से पहले, सालों से मस्क कोशिश कर रहे थे, भारत में अपना काम फैलाने के लिये, पर उन्हें ''एंट्री'' नहीं मिल रही थी। मुकेश अंबानी व सुनील मित्तल भी मस्क को एंट्री देने का सख्त विरोध कर रहे थे।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मार्च। भारती एयरटेल द्वारा एलन मस्क की इंटरनैट सर्विस स्टारलिंक से पार्टनरशिप की घोषणा के एक दिन बाद, अंबानी की कंपनी रियालंस जिओ भी पार्टनरशिप में आ गयी है, साथ ही उसने स्पेस एक्स के साथ एग्रीमेंट की घोषणा भी की है, ताकि स्टारलिंक की ब्रॉड बैंड इंटरनैट सर्विसेज़ भारत के अपने उपभोक्ता को उपलब्ध करवा सके।

स्टारलिंक 100 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। पर, यह कम्पनी भारत में अभी अथॉराइज़ेशन की प्रतीक्षा में है। प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, इसलिए स्टारलिंक को कभी भी स्वीकृति मिल सकती है।

मुकेश अंबानी हमेशा से स्टारलिंक के प्रतिद्वंदी रहे हैं तथा भारत में उसके आगमन का विरोध करते रहे है। पर, बुधवार को अंबानी की कंपनी जिओ ने यू-टर्न ले लिया और कहा कि यह अपने रिटेल आउटलेट्स में न केवल स्टारलिंक के उपकरण बेचेगी, बल्कि कस्टमर सर्विस इंस्टालेशन और एक्टिवेशन के लिए मैकनिज़्म भी तैयार करेगी।

गत कुछ वर्षों में कई बाधाओं का सामना कर चुकी स्टारलिंक अब भारत,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक प्रकरण में स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है

कुछ अखबारों ने पाकिस्तानी सेना के सूत्रों के हवाले से कहा है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, सभी आतंकी मार दिए गए हैं और बंधक छुड़ा लिए गए हैं। दूसरी ओर ट्रेन हाईजैक करने वाले संगठन बी.एल.ए. का दावा है कि उसने 50 बंधकों को मार दिया है और उसकी कैद में 150 बंधक हैं

- एक अखबार का दावा है कि सुरक्षा बलों ने 190 यात्रियों को बचा लिया है, 24 यात्री ही आतंकियों के कब्जे में हैं, साथ ही 30 आतंकियों को मार डाला गया है।
- एक अन्य अखबार ने बताया कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने 100 से ज्यादा पाक सैनिकों व बंधकों को मार दिया है।
- एक अन्य अखबार ने कहा कि बी.एल.ए. ने धमकी दी है कि अगर पाक सेना ने आक्रामक कार्यवाही बंद नहीं की तो सभी बंधकों को मार देंगे।

नई दिल्ली, 12 मार्च। पाकिस्तान में मंगलवार को हएु ट्रेन हाईजैक के दूसरे दिन भारी असमंजस का माहौल रहा वास्तविक स्थिति को लेकर कोई पुख्ता खबर अभी तक नहीं मिली है। विरोधाभाषी दावे किए जा रहे हैं। घटना में भारी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा भेजे हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तानी सेना द्वारा दी गई जानकारी के हवाले से कहा गया है कि, बलूचिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन को छुड़वा लिया गया है और सभी आतंकी मारे गए हैं। बीएलए के कमांडर ने एक वॉइस मैसेज मीडिया में जारी कर बताया कि पाकिस्तानी फौज ने उन्हें घेर लिया है, फायरिंग और गोलीबारी हो रही है, हमारे ग्रुप के लिए दुआ मांगिए।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वैटरनरी असिस्टेंट का अलग काडर में ट्रांसफर करने पर रोक लगायी

- राजस्थान सिविल सेना अधिकरण ने हीरालाल चौधरी की अपील पर आदेश दिया।

जयपुर,, 12 मार्च। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पशु चिकित्सालय, रेनवाल, किशनगढ़ में वेटनरी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत अपीलार्थी के अलग कैडर व पद पर किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अधिकरण ने पशुपालन निदेशक से जवाब तलब किया है। अधिकरण के सदस्य अनंत भंडारी और लेखराज तोसाडा ने ये आदेश हीरालाल चौधरी की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अधिकरण ने कहा है कि अपीलार्थी को वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहने दिया जाए।

अपील में अधिवक्ता रामावतार बोचल्या ने बताया कि अपीलार्थी किशनगढ़ के बधाल पशु चिकित्सालय में वेटनरी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्टालिन सात टीमें भेज रहे हैं, गैर भाजपा शासित प्रदेशों में

हर टीम में तमिलनाडु का एक वरिष्ठ मंत्री व सांसद शामिल होगा और वो वहाँ के मु.मंत्री को स्टालिन का पत्र पेश करेंगे, जिसमें स्टालिन की ओर से 22 मार्च को चेन्नई में आमंत्रित किया गया है, विपक्ष के नेताओं की बैठक में

- बैठक में मुख्य मुद्दा होगा, ''डीलिमिटेशन'' व राज्यों के अधिकार, जिनको केन्द्रीय सरकार धीरे-धीरे ''हथिया'' रही है।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना पश्चिमी बंगाल जायेगा स्टालिन का प्रतिनिधि मंडल तथा राज्यों के ''संवैधानिक अधिकारों'' पर चर्चा करेगा। प्रतिनिधि मंडल शिमला भी जायेगा, वहाँ के कांग्रेस पार्टी के मु.मंत्री को आमंत्रित करने।
- स्टालिन ''डीलिमिटेशन'' के मुद्दे एक जॉइन्ट एक्शन कमेटी भी गठित कर रहे हैं। इस मुद्दे पर एक ''कॉमन स्ट्रेटजी'' के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मार्च। स्टालिन जैसे सशक्त क्षेत्रीय नेता ने खुद अपने लिए भू-राजनैतिक सीमा तय की थी, पर अब वे खुद इसके खिलाफ जाकर राष्ट्रीय राजनीति में पारी खेलना चाहते हैं और देश के सबसे बड़े नेता नरेन्द्र मोदी से संघवाद और राज्यों के अधिकार पर दो-दो हाथ करना चाहते हैं।

केन्द्र सरकार के खिलाफ भारी शब्द युद्ध छेड़ने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केन्द्रीय मंत्रियों से सीधे टकराने और बड़ी चतुराई से केन्द्र बनाम तमिलनाडु के मसले को भाषा विवाद से जोड़ने के बाद स्टालिन पहले ही वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव का कथानक सैट कर चुके हैं।

अपने नवीनतम कदम से उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को परिसीमन और संघवाद के मुद्दे पर केन्द्र के खिलाफ एकजुट कर लिया है। देश के विभिन्न भागों के नेता उनसे सम्पर्क साध रहे हैं। स्टालिन ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, वह तो अपने राज्य में ही खुश थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया था कि राष्ट्रीय मसलों को कांग्रेस देखेगी। इसके अलावा दिल्ली में उन्होंने अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं को भी तैनात कर रखा है। पर अब वे परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं, जो सभी दक्षिण भारतीय राज्यों को प्रभावित करता है। अब स्टालिन ने देश भर के विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं, चाहे वे सत्ता में हों या ना हों, से सम्पर्क साधा है। जैसे ओडिशा की पार्टी बीजू जनता दल। स्टालिन ने सभी को 22 मार्च को आमंत्रित किया, जिसमें केन्द्र सरकार की परिसीमन योजना को नेस्तनाबूद करने के लिए रणनीति तय की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी ऐसे ही विरोध के कारण परिसीमन कई सालों के लिए आगे सरकाना पड़ा था और अब वर्तमान सरकार अगले साल से इसे शुरु कर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है। इस कवायद के तहत द्रमुक का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें राज्य के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'नीट पेपर लीक नहीं हुआ था, अनियमितता की जांच सीबीआई कर रही है'

- शिक्षा राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया।

नयी दिल्ली, 12 मार्च। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में दोहराया कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की परीक्षा नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था, और इस परीक्षा में जो अनियमितता तथा गड़बड़ी हुई, उसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांज की जा रही है।

शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सदन को पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि उच्चतम न्यायालय ने भी अपने आदेश में कहा है कि इस परीक्षा का पेपर लीक होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह कहना कि यह पेपर लीक हुआ है, न्यायालय के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट और उथल-पुथल बरकरार है

पर, फिर भी विश्व की जानी-मानी रेटिंग एजेन्सियां, जैसे मूडीज़ रेटिंग्स, एस. एण्ड पी. ग्लोबल रेटिंग, मॉर्गन स्टैनली आदि, भारत की ग्रोथ रेट के बारे में इतनी आशावादी क्यों हैं?

- मूडीज़ रेटिंग्स, जी.डी.पी. ग्रोथ, 6.5 प्रतिशत से ज्यादा रहने का आकलन कर रहा है, मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ग्रोथ रेट 6.8 प्रतिशत से ज्यादा ही होगी, एस. एण्ड पी. ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार, ग्रोथ रेट 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक रहेगी।
- यह आशावादिता तब है, जबकि, इंडसइंड बैंक के लफड़े के बाद, इंडसइंड बैंक के शेयर की कीमत में 27 प्रतिशत गिरावट आई, तथा अमेरिका में लगातार चर्चा उठ रही है कि फैडरल बैंक ब्याज दर में काफी कमी लाने वाला है, जिससे अमेरिकी पैसा अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लगे और कहीं ''डाइवर्ट'' न हो।
- इकॉनमिस्टों का मानना है कि इंडसइंड बैंक जैसे प्रकरणों के बावजूद, भारत की ग्रोथ सही रास्ते पर है। अतः उसमें गिरावट नहीं आयेगी।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मार्च। ऐसे में जबकि, बाज़ारों के उतार-चढ़ाव ने निवेशकों के आत्मविश्वास को हिलाकर रखा हुआ है, वहीं, इकोनॉमिक फ्रंट से आशावाद का एक संकेत सामने आया है। मूडीज़ रेटिंग्ज़ ने बुधवार को रिलीज़ हुई, ''बैंकिंग सिस्टम आउटलुक-इण्डिया'' शीर्षक वाली अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रियल जी.डी.पी. ग्रोथ बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो जाएगी। आक्रामक सरकारी पूँजीगत व्यय, रणनीतिक कर कटौती और ब्याज दरों में कटौती इस गति को बनाए हुए है।

हाल के हफ्तों में शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव का तूफान आया हुआ है, जिसने घरेलू और वैश्विक स्तर पर निवेशकों के विश्वास को हिला दिया है। इस उथल-पुथल के पीछे कई कारक हैं, जिनमें, प्रमुख बैंकिंग संस्थानों में वित्तीय विसंगतियाँ, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और घरेलू नीतिगत चुनौतियाँ शामिल हैं।

हाल ही में बाज़ार में मची उथल-पुथल का एक महत्वपूर्ण कारण है, इंडसइंड बैंक से संबंधित परेशान करने वाले घटनाक्रम। यह भारत के निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में से एक है। बैंक ने अपनी मुद्रा डैरिवेटिव बुकिंग में अकाउन्टिंग की एक महत्वपूर्ण गड़बड़ी का खुलासा किया है, जिसके कारण आय पर 175 मिलियन डॉलर का अनुमानित प्रभाव पड़ा है- जो एक पूरी तिमाही के लाभ के बराबर है। इस खुलासे के कारण, बैंक के शेयर की कीमत में 27 प्रतिशत की गिरावट आई, जो बैंक के 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से 58 प्रतिशत कम थी।

यह कोई अकेली एकमात्र घटना नहीं है, बल्कि इंडसइंड बैंक के सामने आ रही चुनौतियों की शृंखला में नवीनतम चुनौती है। बैंक जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें माइक्रो लोन डीफॉल्ट में वृद्धि, गवर्नैंस से संबंधित चिंताएं और बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी का इस्तीफा शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक का यह निर्णय, कि सी.ई.ओ. सुमंत कथपालिया का कार्यकाल तीन साल के प्रस्तावित कार्यकाल के बजाय एक साल ही बढ़ाया जाएगा, ने निवेशक के विश्वास को और भी कम कर दिया है।

घरेलू बैंकिंग संकट को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने और बढ़ा दिया है। अमेरिका में आर्थिक मंदी की संभावनाओं को लेकर बढ़ रही चिंता के कारण व्यापारी, फैडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में और अधिक कमी करने की आशंका जता रहे हैं। माना जा रहा है कि इस साल 80 बेसिक पॉइंट तक की कमी की जाएगी।

बाज़ार की परेशानियों को घरेलू नीति चुनौतियाँ और बढ़ा रही हैं। व्यापारियों ने जटिल कर संरचनाओं और नौकरशाही अवरोधों को लेकर नाराज़गी व्यक्त की है, जिन्हें अक्सर ''टैक्स टैररिज़्म'' कहा जाता है। फोकसवैगन जैसी कंपनियों को भारी टैक्स डिमाण्ड का सामना करना पड़ा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली एवं धुलंडी की शुभकामनाएं

जयपुर, 12 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली एवं धुलंडी (13 व 14 मार्च) के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने कहा कि होली का यह त्योहार जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के परिचायक हैं। रंगों और खुशियों से लबरेज यह पर्व हमें आपसी भाईचारे, एकता और सद्भाव को बढ़ाने की सीख देता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आव्हान किया कि वे आपसी प्रेम, सौहार्द, सामाजिक समरसता के साथ रंगों के इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाएं और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें।